SHRI MOHAN DHARIA: Whatever is needed by our country, we would very much like to import from the friendly countries, as I have stated in this House. While the protectionist trends are on the rise, we would like to import more and more from the developing countries and export to them also whatever is needed by them. This is how we would like to have that sort of cooperation.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केनिया में जो उद्योग लगने वाला है, इसमें जो माल तैयार होगा, क्या इसके लिये मार्केट हमें ढूंढना पड़ेगा ? क्या इस प्रकार के उद्योग और भी किन्हीं देशों में लगाने की आपकी योजना है ? यदि हां, तो किन-किन देश में सरकार के प्रस्ताव हैं और इसकी मूल शर्तें क्या हैं और कब तक इन शर्तों को निभायेगी हमारी सरकार ?

श्री मोहन धारिया : जब कोई उद्योग लगाया जाता है तो यह सब ध्यान में लेकर लगाया जाता है कि मार्केटिंग फैसिलिटी कैसी है, यह उद्योग कामयाब होगा या नहीं । यह सब देखना पड़ता है । जब तक वायेबिलिटी टैस्ट नहीं होती तब तक कोई उद्योग लगाया नहीं जाता ।

अब तक 343 ऐसे ज्वायन्ट वैन्चर मंजूर किये हैं जिसमें से 107 चालू हो चुके हैं और 89 ऐसे हैं जो कि कार्यान्वयन की स्टेज में हैं । यह लिस्ट तो बड़ी लम्बी होगी, क्योंकि काफी देशों में हमारे ज्वायन्ट वेंचर जारी हैं, लेकिन जिस वक्त हम ज्वाइन्ट वैंचर की इजाजत देते हैं तब हमारे मुल्क में जो मशीनरी पैदा होती है, स्पेयर पार्ट पैदा होते हैं हमारे यहां जो नौजवान हैं, जिनको वहां काम मिल सकता है, यह सब ख्याल में लेकर हम ज्वाइन्ट वैन्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं ।

SHRI PURNANARAYAN SINHA : It is well known that Kenya is a traditional competitor with India in the export of tea. Srilanka and Kenya are offering tea to the international market and Indian tea is being priced out. In view of relations of joint ventures, is it possible to start joint ventures in commerce? In order to earn more foreign exchange, we are going to increase production of tea, but Kenya along with Srilanka are our competitors. Is it, therefore, possible to start joint ventures in business so that our tea could be sold at a better price and we could earn more foreign exchange?

MR. SPEAKER: The only connection is the word 'Kenya, nothing more.

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, here the whole problem is that there are some articles like tea, jute and iron ore where there are certain countries which are the exporting countries and while I was in Kenya I had discussed the matters with the Kenyan Ministers. Before that I was in Colombo also and I discussed with the President of Sri and also the Ministers of Sri Lanka, and by and large there could be an agreement whereby we can have at least a minimum price for the exports of tea to be met. I am having my dialogue in that direction and it will be very difficult to say anything at this stage, but I do feel that in the case of coffee, in the case of jute, in the case of tea and in the case of our agricultural products or industrial products or even iron ore or some other minerals, wherever we can get better price, it should be our endeavour to get and it is in this context, it may not be possible to have any joint venture as such, but there could be a proper understanding with a view to get better foreign exchange.

**Draft Paper on National Tourism Policy**

*272. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 471 on 22nd December, 1978 regarding National Tourism Policy and state:

(a) whether Government have received the views of the concerned authorities of Government on the draft paper on the National Tourism Policy;

(b) if so, what are their views; and

(c) whether the draft paper has been finalised, if so, when it will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Policy statement on tourism revised after taking into

account the views of the Ministries and Departments consulted is in the process of finalisation and will be laid on the Table of both Houses of Parliament as soon as it is approved by Government.

**श्री दुर्गा चन्द** : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि पालिसी स्टेटमेंट आन टूरिज्म रिवाइज हुआ है और कुछ दिनों के बाद जब गवर्नमेंट इस को कंसिडर कर लेगी तो सदन के पटल पर रख दिया जायेगा। मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि इस पालिसी के सैलिएंट फीचर्स कौन-कौन से हैं जो आपने ड्राफ्ट किया है? मेन फीचर्स इस नेशनल पालिसी के क्या हैं?

**श्री पुरुषोत्तम कौशिक** : अध्यक्ष महोदय, यह तो पालिसी स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा जायेगा तो माननीय सदस्य को मालूम हो जायगा। ऐसे भी जिस दिशा में पर्यटन को विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वह तो आप को मालूम है कि इस पर्यटन को आम आदमी के लिए भी सुलभ बनाने की कोशिश हो रही है। इस दृष्टि से इस के पहले जो चार और पांच सितारे वाले होटल्स पर बहुत जोर दिया जाता था वह न दे कर के उस के अतिरिक्त कम कीमत वाले होटल बनाने की कोशिश की जा रही है जो साफ सुथरे हों जिस में देश के भी कम आय वाले लोग ठहर सकें और विदेशों के भी इस तरह के लोग जो बुद्धिजीवी हैं और जो देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को और देश को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की पहुंच के अन्दर भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश विभाग के द्वारा की जा रही है। इसके साथ-साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यटन केन्द्र हैं उन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और उन को प्रोजेक्ट करने की दिशा में समुचित कदम उठाए जायं। ये चीजें मुख्य रूप से उस में हैं।

**श्री दुर्गा चन्द** : माननीय मंत्री जी ने डोमेस्टिक टूरिज्म के मुताल्लिक तो कुछ प्रकाश डाला है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि हमारे देश में इंटरनेशनल टूरिज्म के भी बहुत बड़े पोटेंशियल हैं और उस की बढ़ोत्तरी के लिए स्कोप है तो क्या आप जो यह नेशनल पालिसी फ्रेम कर रहे हैं इस में जापान, स्पेन और स्विटजरलैण्ड जैसे देशों के बारे में भी स्टडी की गई है जो कि टूरिज्म के लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं और काफी वहां की एकोनोमी को डेवेलप करने में उन का स्थान है, क्या उन देशों में जो डेवलप्ड टूरिज्म है उस की भी स्टडी की गई है ताकि इंटरनेशनल टूरिज्म हमारे देश में भी डेवलप कर सके?

**श्री पुरुषोत्तम कौशिक** : स्वदेशी पर्यटन की तरफ ध्यान देने की बात मैं कहता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो विदेशी पर्यटक हैं उन को हम पूरी तरह से नजरअन्दाज करें। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि खास तौर से जो पड़ोसी बुद्धिस्ट देश हैं, उन देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से जो बौद्ध केन्द्र हमारे देश में हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने का काम चल रहा है। उस के लिए नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ डिजाइन्स की सेवाएं भी ली जा रही हैं और उसका मास्टर प्लान भी तैयार करने का काम हो रहा है। नालन्दा और कुशीनगर इन दो स्थानों के मास्टर प्लान तैयार हो गए हैं। अब उन पर अमल करने का काम हो रहा है। इस तरह से ये जो केन्द्र हैं इन पर विशेष रूप से ध्यान दे कर उन को विकसित करने का काम किया जा रहा है।

**श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : टूरिज्म का देश में जितना विकास होना चाहिये नहीं हो रहा है। जिस देश की सस्कृति को हमें विदेशियों को दिखाना चाहिये उसको दिखाया नहीं जा रहा है। एक परवर्टिड सस्कृति के दर्शन ही उनको होते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बाहर वाले बहुत गलत चीज ले कर जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? केवल खजुराहो ही देश की सस्कृति नहीं है। सांप नचाने वाले, भालू नचाने वाले आदि को उनको दिखाए जाते हैं और जिन को हम से पहले अंग्रेज भी दिखाया करते थे इन पर ही आज भी जोर दिया जाता है और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अभी भी इनको पेश किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो हमारे टूरिज्म के सेंटर हैं, बनारस है, हरिद्वार है, दूसरी जगहें हैं जहां बहुत ज्यादा विदेशी जाते भी हैं वहां जो गदगी है वहां जो एक सडाध आती है उसको दूर करने की तरफ भी क्या आपका ध्यान है? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो साल में इस तरह की चीजों में आपने क्या सुधार किया है?

**श्री पुरुषोत्तम कौशिक** : खजुराहो का अपना एक महत्व है, इसका अपना एक आकर्षण है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खजुराहो के साथ-साथ कृष्ण लीला की जो ब्रज भूमि है, हल्दी घाटी है, ऐसे स्थानों का भी विकास करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। उनके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ही हम यह सब कर रहे हैं। पूरा प्लानिंग हम कर रहे हैं और उसके अनुसार उनको विकसित करने का काम करेंगे।

जहां तक सफाई का सवाल है, पर्यटन विभाग के द्वारा सभी काम हाथ में नहीं लिये जा सकते हैं। यह स्थानीय संस्थाओं का काम है। उनका सहयोग भी हम ले रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां जाते हैं वे किसी तरह की गलत धारणा ले कर न आएं, मन में अच्छे विचार ले कर आएं इस दृष्टि से स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से उनको साफ सुथरा रखने की दिशा में भी हम पहल कर रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह शास्त्री : मंत्री महोदय ने दो जगहें बताई हैं कुशीनगर और राजगीर। लेकिन सांची के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां से मांग आई भी है पैसे के लिए ताकि वहां पर टूरिज्म को डिवैलप किया जा सके लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे हैं।

धाना फारेस्ट्स जितने बड़े फारेस्ट हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं। वहां वन सम्पदा बहुत है। वहां के शेर खास तौर से देखने लायक हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : कुशीनगर और राजगीर के बारे में मास्टर प्लान बन गया है। जहां तक धाना और सांची का सम्बन्ध है, वहां जो आवास व्यवस्था है उसको विकसित करने का काम हो रहा है। सांची में और एक्सपेंशन का काम हाथ में ले रहे हैं। धाना में भी एक फारेस्ट लाज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**Purchase of F.C.V. Tobacco by State Trading Corporation**

*273. SHRI P RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Trade Corporation bought more than 10 million Kgs. of F.C.V. tobacco in 1978;

(b) whether it is a fact that China bought F.C.V. tobacco for our Country in November and December, 1978;

(c) whether it bought the above tobacco from State Trading Corporation; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) STC's total purchase of FCV tobacco during 1978, both on its commercial account and Government account, was a little over 12 million Kgs.

(b) and (c). Two private firms from Andhra Pradesh sold FCV tobacco of various grades to China during 1978.

(d) As export of tobacco is not canalised through the State Trading Corporation, the buyer has the choice to select suppliers in India.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I would like to know whether it is a fact that STC has bought inferior tobacco. Is it the reason why China has bought from private persons? Why is it that the Government allowed this? Why is it that the Government has not canalised tobacco through STC?

THE MINISTER OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES OND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): As the House is aware, the production of tobacco in our country is much in proportion compared to the requirements of the country and even for export purposes. Anybody can export tobacco and we have not canalised the export of tobacco through STC so that it boosts up production and to give the producers a fair price. We have kept it open. STC is also having its own exports. It is the choise of the buyer. If they have made their choice, there is nothing to grudge about it.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: In the Government adopting the policy of giving the 'veto power' to the buyer for all commodities?

SHRI MOHAN DHARIA: It all depends—Wherever we have them in abundance naturally we would like all such commodities to be purchased on a wider scale; but if we are having scarce commodities we cannot do that.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: The Government allows foreign buyers to purchase tobacco directly from some private companies. Will the Government announce a quota of tobacco for various companies with respect to foreign purchases, because the farmer is not getting a proper price and the price they are paying the businessman is not known. They are paying a low price to the farmers.